

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- डॉ० सौम्या झा

आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 13/2026 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

मैसर्स के.डी.लोजिस्टिक जरिये प्रोपराईटर कासम खान पुत्र श्री हारून जाति मेव मुसलमान ई-5, जी-3, बीडीआई आन्दा झिवाणा पुलिस थाना चौपनकी जिला खैरथल हाल खोहरी पुलिस थाना तावडू जिला नूह मेवात हरियाणा

बनाम

राज० सरकार जरिये लोक अभियोजक अधिकारी (न्यायालय ए०डी०जे. कोर्ट दौसा जिला दौसा)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 18/2024

पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा

अं० धारा 3, 5, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995

उपस्थित:1. श्री जयन्त कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 17.04.2026

- संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा दिनांक 10.01.2024 को 30 गोवंश भरकर ले जा रहा अशोक लीलेण्ड ट्राला वाहन संख्या RJ 32 GC-8733को अभियोग संख्या 18/2024 अंतर्गत धारा 3, 5, 8, 9, 10 गोवंश अधिनियम में जब्त किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा उक्त अशोक लीलेण्ड ट्रालावाहन संख्या आरजे 32जीसी 8858 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।
- अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि उनवानी प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है जिसका एफआईआर नंबर 18/2024 है। उक्त उनवानी प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली द्वारा चालान पेश किया जा चुका है जो माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय दौसा में बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम कासम खान विचाराधीन है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी का वाहन ट्रक नंबर आरजे 32 जीसी 8733 पुलिस थाना कोतवाली ने जब्त कर रखा है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी उक्त वाहन का जरिये प्रापराईटर फर्म मै. के. डी. लोजिस्टिक पंजीकृत स्वामी है। इसलिए उक्त वाहन को सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त उनवानी प्रकरण में उक्त वाहन की पुलिस थाना कोतवाली दौसा को कोई आवश्यकता नहीं है तथा वाहन पडा-पडा खराब हो रहा है तथा प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी श्रीमान के सन्तुष्ट सुपुर्दनामा व जमानतीनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा श्रीमानजी की सेवामें प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को वाहन ट्रक संख्या संख्या RJ 32 GC8733सुपुर्दगीनामा पर दिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में वाहन चालक असरू का देहान्त हो गया है। इस बाबत वाहन चालक असरू का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।
- राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 11.01.2024 को पुलिस थाना कोतवाली दौसा द्वारा वाहन सं० संख्या संख्या RJ 32 GC8733 को 30 गोवंश भर कर ले जा रहे वाहन को जब्त किया गया। उक्त वाहन में गोवंश को ठूस-2 कर भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार गोवंशीय पशुओं को कूरतापूर्वक वाहन में वध के प्रयोजन से परिवहन निर्यात करना पाया गया। प्रकरण के मुल्लिम

जिला कलक्टर दौसा



कासम खान को प्रकरण के विरुद्ध अपराध धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गोवंश अधिनियम का प्रमाणित पाये जाने पर मुज्जिम को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.12.2025 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में चालान पेश किया जा चुका है।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. इस संबंध में राज. गोवंशीय पशु अधिनियम की धारा 6 ए के प्रावधान निम्नानुसार है जो अवलोकनीय है:—

“ 1 6-A. Confiscation of the means of conveyance.- (1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.

(2) Where any means of conveyance referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Competent Authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the Competent Authority, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Competent Authority that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Competent Authority may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Competent Authority and the matter shall be referred to the State Government by the Competent Authority for making such orders regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section, the owner of the means of conveyance referred to in sub-section (1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance:

Provided also that an owner of a means of conveyance shall not be given option under the preceding proviso, if he had been given option under that proviso at an earlier occasion.

(3) Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

(4) Where the Competent Authority is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.

(5) Any order of confiscation made by the Competent Authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.”.

7. हमने पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।


जिला कलेक्टर, दौसा



- विश्लेषण एवं विवेचन: मैंने प्रकरण की पत्रावली, विवेचना रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट, चालान एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परीक्षण किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।
 - यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि वाहन ट्रक संख्या **RJ 32 GC8733** का उपयोग 30 गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन हेतु किया गया। पुलिस दल द्वारा मौके पर वाहन में पशुओं को रस्सियों से बंधी अवस्था में, मुँह एवं पैर बंधे हुए तथा घायल अवस्था में पाया गया। यह अधिनियम की धारा 5 एवं 6 का स्पष्ट उल्लंघन है।
 - आरोपी कासम खान पुत्र हारून की पहचान हुई है तथा अधिनियम की धारा 5, 6, 8 एवं 9 के अन्तर्गत चालान दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत किया गया है।
 - उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाहन का उपयोग अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने हेतु किया गया है। ऐसे वाहन को सुपुर्दगीनामे पर वापस लौटाना अधिनियम के उद्देश्यों एवं भावना के विपरीत होगा।
 - राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 6 ए जिला कलेक्टर को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित करने में प्रयुक्त वाहन को जब्त एवं जप्त (**confiscate**) करने का आदेश दे सकता है। धारा 6 ए के अनुसार, जब कोई वाहन गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन अथवा वध हेतु प्रयुक्त पाया जाता है, तो ऐसे वाहन की जब्ती (**confiscation**) का आदेश पारित किया जा सकता है।
 - प्रकरण के तथ्य एवं संलिप्तता: वाहन ट्रक (रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ 32 GC8733**) को दिनांक 10.1.2024 को जब्त किया गया था, जिसमें कुल 30 गोवंश भरे हुए मिले थे, जिनका अवैध रूप से गोकशी के लिए परिवहन किया जा रहा था। यह अपराध धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत आता है।
 - वाहन स्वामी की भूमिका: अनुसन्धान में वाहन स्वामी के खिलाफ धारा 6, 8 गौवंश अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। मुल्जिम कासम खान पुत्र हारून को गिरफ्तार कर चालान दिनांक 18.12.2025 को पेश किया जा चुका है।
 - अधिहरण (**Confiscation**): जब्तशुदा वाहन का उपयोग गोकशी के लिए अवैध गोवंश परिवहन जैसे गंभीर अपराध में हुआ है इस अधिनियम के तहत, कलेक्टर को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह संतुष्ट हो जाए कि वाहन का उपयोग अपराध में हुआ है, तो वह उसे अधिहरण (**Confiscation**) करने का आदेश दे सकता है।
 - अधिहरण की कार्यवाही: चूंकि वाहन स्वामी स्वयं अपराध में संलिप्त पाया गया है, यह प्रथम दृष्टया अपराध में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण का मामला बनता है, लेकिन अंतिम निस्तारण न्यायालय में विचाराधीन है।
 - निष्कर्ष: प्रकरण की गंभीरता के मद्देनजर, जब्तशुदा वाहन को इस आदेश द्वारा अधिहरण करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन आवेदक को पर्याप्त जुर्माना और जमानतें जमा कराकर इसे अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है।
- आदेश (Operative Order):**
उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है:


जिला कलेक्टर, दोसा



- वाहन ट्रक नम्बर **RJ 32 GC8733** का उपयोग राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) नियम 1955 के तहत गंभीर अपराध में होना प्रमाणित होने के कारण, उक्त वाहन को अधिहरित (**Confiscated**) किया जाता है।
 - सशर्त सुपुर्दगी द्वारा रिहाई का अधिकार (**Right of Release on Payment of Fine**): अधिहरण के आदेश के बावजूद, आवेदक मैसर्स के0 डी0 लोजिस्टिक जरिये प्रोपराईटर कासम खान पुत्र हारून को निम्न शर्तों और जुर्माना जमा कराने पर वाहन नम्बर **RJ 32 GC 8733** को अस्थायी रूप से सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है:
 - जुर्माना (**Fine**): आवेदक वाहन के मूल्य (जो कि बीमा के दस्तावेजों से सिद्ध होता है) का 70 प्रतिशत अर्थात 4,90,000/-रु0 (अक्षरे चार लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का जुर्माना (**Fine**) इस न्यायालय में जमा कराएगा। जुर्माना राशि जमा नहीं कराये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा खुली नीलामी के द्वारा वाहन का निस्तारण किया जायेगा।
 - बंध पत्र (**Surety Bond**): आवेदक एक लाख रुपये (₹1,00,000/-) का व्यक्तिगत बंध पत्र (**Personal Bond**) तथा दो सक्षम एवं संतोषजनक जमानतें (₹1,00,000/- की) इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा
अन्य शर्तें:
 - जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। (इस हेतु वह अपना स्थाई पता, दूरभाष नंबर, ई मेल एड्रेस, व व्हाट्सअप नंबर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे)
 - छायाचित्र एवं सुपुर्दनामा: आवेदक सुपुर्दगी से पूर्व जब्तशुदा वाहन के नवीनतम फोटो (चारों दिशाओं से) और एक विस्तृत सुपुर्दनामा (**Supurdagi Nama**) न्यायालय में जमा कराएगा।
 - वाहन का विक्रय/हस्तांतरण निषेध: आवेदक सक्षम न्यायालय के आगामी आदेश के बिना उक्त वाहन को बेचेगा/हस्तांतरित करेगा या उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
 - आवश्यकता पर प्रस्तुति: आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब भी संबंधित न्यायालय प्राधिकारी द्वारा वाहन को प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाए, वह वाहन को उसी स्थिति में तत्काल प्रस्तुत करेगा।
8. निर्णय की प्रति पालनार्थ पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।
- निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ० सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा